



मुख्यमंत्री कार्यालय में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया

इस्तीफे की घोषणा के साथ डॉ. किरोड़ी ने एक्स पर लिखा "रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन ना जाई"

- किरोड़ी ने बताया कि, उन्होंने 5 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस्तीफा भेज दिया था और 25 जून को व्यक्तिगत मुलाकात कर इस्तीफा दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने अस्वीकार कर दिया था

- डॉ. किरोड़ी ने कहा कि, अपने क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को नहीं जिता पाने पर मैंने इस्तीफा देने का प्रण लिया था। इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे पार्टी संगठन एवं सरकार से कोई शिकायत नहीं है।

- डॉ. किरोड़ी ने इस्तीफा मेल करने के बाद पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के प्राक्टोटोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और मंच से इस्तीफा देने की सार्वजनिक घोषणा की।

जयपुर, 4 जुलाई। राजस्थान की भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार सरकार के सभी सभ्य पदों से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद से ही डॉ. किरोड़ी लाल के इस्तीफे की अटकलें चल रही थीं। पूर्वी राजस्थान की सीटों पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल लोकसभा चुनाव परिणाम आने के साथ ही सरकारी सुविधाएं छोड़ दी थीं।

बता दें कि किरोड़ी मीणा सोशल मीडिया सहित कई मंचों पर इस्तीफा देने के संकेत दे रहे थे। अब उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंत्री पद से त्यागपत्र भेज दिया। इस्तीफा देने के साथ ही डॉ. किरोड़ी ने सुबह 10:50 पर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक आमचर्चितमानस चोपड़ा पोस्ट की "रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन ना जाई।"

इससे पहले भी वो इन्हीं पंक्तियों के जरिए अपने इस्तीफे के संकेत दे चुके थे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने 5 जून को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया था। उसके बाद 25 जून को मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा था। लेकिन उन्होंने इस्तीफे को पूरी तरह से ठुकरा दिया। जिसके बाद मैंने उन्हें इस्तीफा मेल कर दिया है और इसकी घोषणा आज कर दी है। उन्होंने कहा- "मुझे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस्तीफा देने से मना किया था, लेकिन मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ।"

मीणा ने कहा जैसा कि आप लोग जानते हो कि अथक परिश्रम के बाद भी मैं अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। मैंने चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी। उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दिन रात मैंने जनता के लिए संघर्ष किया। ना दिन देखा ना रात। लेकिन जनता ने मेरी नहीं मानी। मुझे निराश किया। इसलिए मैंने अंतरात्मा की आवाज पर पद छोड़ दिया।

राहुल गांधी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
समस्याएं सुनीं। ये मेहनती मजदूर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनके जीवन को सरल और भविष्य को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है।

केजरीवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
वाई चंद्रचूड़ को लिखे लेटर में वकीलों ने कहा है कि केजरीवाल की जमानत अर्जी पर जज फैसला लेने में देरी कर रहे हैं।

मुकेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
टन' अनुग्रह किया है, सिवाय उन अवसरों के, जब मुकेश अंबानी उन्हें पीछे छोड़ दिया है। आगामी समय इस दृष्टि से रोचक रहेगा।

आदिवासियों का "डी.एन.ए. टैस्ट" करवाने के बयान पर मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर, 4 जुलाई। आदिवासियों को हिंदू बताने और उनका "डी.एन.ए. टैस्ट" करवाने के तथाकथित बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को दिनभर विधानसभा में धिरे नजर आए। कांग्रेस और आदिवासी विधायकों ने दिनभर सदन में हंगामा करते हुए मदन दिलावर से माफी मांगवाने और उनका इस्तीफा दिलवाने की मांग रखी। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा इतना बढ़ा कि, विपक्षी विधायक वैल ने उतर आए और सत्ता पक्ष के साथ गुथ्यमगुथ्या होते-होते बचे। आनन-फानन में विधानसभा के मार्शलों ने मोर्चा संभाला और उन्हें एक-दूसरे से अलग किया। हालात बिगड़ते देख विधानसभाध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी को 2 बार में सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में जब सदन पुनः जुटा तो

सदन में दिनभर भारी हंगामा करने के बाद विपक्ष ने दोपहर में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर वॉक आउट किया

- एक बार तो हालात इतने बिगड़े कि विपक्षी विधायक वैल ने उतर आए और सत्ता पक्ष के साथ गुथ्यमगुथ्या होते-होते बचे। गनीमत रही कि, आनन-फानन में विधानसभा के मार्शलों ने मोर्चा संभाला और उन्हें एक-दूसरे से अलग किया।
- स्पीकर डॉ. वासुदेव देवनानी को 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में जब सदन पुनः जुटा तो स्पीकर ने दोनों पक्षों को संयम रखने की नसीहत दी और कहा कि, "विधानसभा के इतिहास में आज सदन की कार्यवाही तार-तार होते बची है।"

आदिवासी हिंदू नहीं हैं, तो मेरा कहना था कि आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे।

आदिवासी ही हैं। क्योंकि हम आदिकाल से यहां रहते आए हैं। मैं आदिवासी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जब पत्रकार ने दोबारा पूछा कि वो तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो मैंने कहा, "वह प्रासंगिक है कि नहीं कि वंशावली दिखवा लेंगे!" मंत्री के इस स्पष्टीकरण से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सभी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर वैल ने आ गए। प्रदर्शन करते हुए दिलावर की ओर विपक्षी सदस्यों को बढ़ते हुए देख सत्तापक्ष के सदस्य और मंत्री भी वैल में आ गए।

आदिवासी ही हैं। क्योंकि हम आदिकाल से यहां रहते आए हैं। मैं आदिवासी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जब पत्रकार ने दोबारा पूछा कि वो तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो मैंने कहा, "वह प्रासंगिक है कि नहीं कि वंशावली दिखवा लेंगे!" मंत्री के इस स्पष्टीकरण से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सभी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर वैल ने आ गए। प्रदर्शन करते हुए दिलावर की ओर विपक्षी सदस्यों को बढ़ते हुए देख सत्तापक्ष के सदस्य और मंत्री भी वैल में आ गए।

पार्टी के तीनों विधायकों के साथ ही कांग्रेस के सभी विधायकों ने खिल में आकर मदन दिलावर के बिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने मंत्री दिलावर से उनके बयान पर माफी मांगने की मांग उठाई और इस्तीफा देने के लिए कहा। इसी बीच सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ऐसे में प्रसन्नकाल के दौरान कुछ ही सवालियों के ओर से उठाए गए पूरे प्रश्नों के जवाब भी हंगामे की भेंट चढ़ गए।

ज्ञातव्य है कि मदन दिलावर के जिस कथित बयान पर हंगामा हो रहा है वह यह है कि "आदिवासी हिंदू हैं या नहीं यह उनके पूर्वजों से पूछेंगे या वंशावली लिखने वालों से पूछेंगे वो कौन हैं। यदि हिंदू नहीं है तो उनका डी.एन.ए. टैस्ट करेंगे।"

बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल सी वी आनंद बोस के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये हैं

नई दिल्ली, 4 जुलाई (वार्ता)। पश्चिम बंगाल राज्यपाल की एक महिला कर्मचारी ने वहां के राज्यपाल सी वी आनंद बोस के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में महिला दावा किया कि राज्यपाल को दी गई संवैधानिक प्रतिकक्षा के कारण वह उपचारविहीन हो गई है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से गृहार लगाई है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने के लिए वह पश्चिम बंगाल पुलिस को आवश्यक निर्देश दे। याचिका में उक्त प्रावधान का हवाला देते हुए दलील दी गई है कि ऐसी शक्तियों को पूर्ण नहीं समझा जा सकता, जिससे राज्यपाल को ऐसे कार्य करने का अधिकार मिल जाए जो अवैध हों या जो संविधान के भाग तीन की बुनियाद पर प्रहार करते हैं। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायतों को उजागर करते हुए

राजभवन को एक शिकायत भी लिखी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित निष्क्रियता बरतते हुए उसे अपमानित किया गया और मीडिया में उसका मजाक उड़ाया गया। उसे राजनीतिक हथियार बताया गया, जबकि उसके आत्मसम्मान को कोई सुरक्षा नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं और संवैधानिक छूट की आड़ में राज्यपाल को किसी भी तरह से अनुचित तरीके से कार्य करने और लैंगिक हिंसा करने की अनुमति नहीं है, जबकि देश के

हर दूसरे नागरिक को ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है। शिकायतकर्ता महिला ने याचिका में कहा है कि यह (विशेष अधिकार) सीधे तौर पर संविधान के तहत उसके साथ ही (याचिकाकर्ता) सहित प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए मौलिक अधिकारों पर हमला करता है। याचिका में कहा गया, इस मामले में पीड़िता (याचिकाकर्ता) को झूठा बनाना, जबकि यह सुनिश्चित करना कि आरोपी/माननीय राज्यपाल खुद बेदाग हैं। सत्ता का ऐसा अनियंत्रित प्रयोग एक गलत मिसाल कायम करेगा, जिससे यौन पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिलेगी। यह संवैधानिक लक्ष्य का पूर्ण उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता ने दो मई 2024 को संबोधित प्रभारी अधिकारी को एक लिखित शिकायत दी, जिसमें राज्यपाल पर बेहतर नौकरी देने के बहाने उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया।

इस्तीफे का तात्कालिक कारण?

जयपुर, 4 जुलाई। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की सार्वजनिक घोषणा गुरुवार को सुबह की लेकिन सरकार ने बुधवार रात को ही विधानसभा में जवाब देने के लिए दो मंत्रियों के बीच उनके विभागों का बंटवारा कर दिया। जानकारी के अनुसार, डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि मंत्री के पद से 5 जून को ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेज दिया था और 25 जून को उन्होंने खुद मिलकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस्तीफा सौंपा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। लेकिन विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उनके

- बताया जाता है कि, विधानसभा में डॉ. किरोड़ी के विभागों से संबंधित सवालों का जवाब देन के लिए राज्य सरकार ने उनके विभागों को दो मंत्रियों में बांट दिया था, इसलिए किरोड़ी ने आनन-फानन में इस्तीफे की अधिकृत घोषणा कर दी।

विभागों से सम्बंधित सवालों के जवाब देने के लिए सरकार ने बुधवार रात दो अन्य मंत्रियों को विभागों की जिम्मेवारी सौंप दी तथा इसके आदेश भी जारी कर दिए थे।

सूत्रों का कहना है कि शायद इसी कारण से डॉ. किरोड़ी ने गुरुवार सुबह इस्तीफा मेल कर दिया और सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दे दी।

सरकारी सूचना के अनुसार आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग के सवालों का जवाब देते और राज्य मंत्री के.के. विरनोई कृषि विभाग, जन अधिकांश निराकरण विभाग और उद्यान विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत होंगे।

प्र.मंत्री की आठ व नौ जून की रूस यात्रा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उद्देश्यों के अनुकूल भी है। वे पश्चिम दुनिया के पसंदीदा उदार लोकतांत्रिक मॉडल में संघर्ष को लेकर एक वैकल्पिक सिस्टम प्रस्तुत करना चाहते हैं।

चीन के प्रभुत्व वाली किसी व्यवस्था के प्रतिरोध में पारम्परिक मतभेदों के अलावा बेलायत को एस.सी.ओ. में शामिल किया जाना, शायद भारत के बर्दाश्त की हद थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सम्मेलन में भाग लेने आए देशों से एक अनुरोध कर अपने कूटनीतिक इरादे जाहिर कर दिए थे-उन्होंने इन देशों का आह्वान किया था कि वे अमेरिका की अधिकृत व्यवस्था से परे अपने उद्देश्यों को लेकर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ें और विकास के अधिकारों के लिए संघर्ष करें।

शी ने आज ही कहा कि एस.सी.ओ. के सदस्य देश अपनी सुरक्षा संरचना में "बाहरी ताकतों" के हस्तक्षेप के किसी भी प्रयास का प्रतिरोध करें। हालांकि, इसमें अन्तर्निहित विरोधाभास था इस फोरम में रूस की उपस्थिति का होना, जबकि रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर बिना किसी कारण के आक्रमण कर चुका है। रूस के आक्रमण की पृष्ठभूमि में जब इस संगठन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को स्पष्ट कर दिया था कि "नह समय युद्ध का नहीं बल्कि मतभेदों और विवादों को वार्ता एवं बातचीत के जरिए हल करने का है। तब मोदी के इस सैंसेज की यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर पुतिन से पहली प्रत्यक्ष झड़प के रूप में प्रशंसा की

गई थी। मोदी ने उसके तुरंत बाद अमेरिका का दौरा किया था, जहां वॉशिंगटन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनके सम्मान में वाइट हाउस में राजकीय "डिनर" रखा गया। उन्हें अमेरिका की सीनेटर्स को संबोधित करने का सुअवसर भी प्रदान किया गया।

अब एक बार पुनः भारत को रूस के साथ रक्षात्मक भूमिका निभानी है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका व पश्चिमी देशों की सत्ता से उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से त्रस्त है। इसीके चलते रूस को पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु इस बार भारत ने पश्चिमी देशों के इस खेल में शरीक होने से मना कर दिया था। बल्कि भारत ने रूस से कम

मूल्य पर तेल खरीदना जारी रखा जो भारत के हित में रहा था। इस तरीके से भारत रूस को मदद करने में प्रमुख भागीदार रहा।

भारत के हित भी रूस के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वह भारत को मुख्य रूप से सेना के लिए अस्त्र-शस्त्र सिस्टम की आपूर्ति करता रहा है। यह इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हिमालय की सीमाओं पर चीन से शत्रुता का सामना कर रहा है। इसलिए भारत को विभिन्न कार्यों के मुद्देनजर बहुत ही मुश्किल व सूक्ष्म कूटनीतिक खेल अपने हितों की रक्षा रखना है।

भारत के प्रधानमंत्री इन सब परिस्थितियों के चलते एस.सी.ओ. की बैठक में भाग नहीं लेकर सीधे रूस की यात्रा पर जा रहे हैं।